२
उद्घाटन सत्र

'इसीमोड' की अर्चना कार्की ने उद्घाटन समारोह में कार्यशाला के सहभागियों एवं अतिथियों का स्वागत किया । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय के राज्य मंत्री श्री भक्त बहादुर रोकाया उद्घाटज सत्र के सभापति थे । अर्चना जी ने अन्य अतिथियों को अपना-अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया । इन अतिथियों में थे सर्वश्री एगबर्ट पेलिङ्ग (इसीमोड के महानिर्देशक) सुश्री केसांग छुन्न्यलापा (सहायक आवासीय प्रतिनिधी, यु.एन.डी.पी. नेपाल), माधव पौडेल (सभापति, जिला विकास समिति, नेपाल, और सभापति, ललितपुर जिला विकास समिति) हरिप्रसाद न्यौपाने (सभापति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, नेपाल) ।

अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व अर्चनाजी ने पूर्व दिवस में हुए अनौपचारिक 'मिट्टी मिलन' समारोह के विषय में विस्तार से बताया । यह 'मिट्टी मिलन' समारोह अनौपचारिक तो था लेकिन प्रतीक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण था । उन्होंने कहा कि घडे पर बनी हुई आकृति पर्वत और पर्वतीय जीवन को प्रदर्शित करती है । घडे पर बने हुए चित्र जिसमे कि एक दूसरे के हाथों को गोलाकार और अविच्छिन्न रूप से पकडे हुए पुरूष और महिलाओं का चित्र जहाँ एक और पर्वतीय जीवन के सामान्य समस्याओं को दिखाता है वहीं यह चित्र उन सामान्य समस्याओं से एकजुट होकर जूझने की

स्थानीय विकास एवं वन तथा भू-संरक्षण विभाग के माननीय मंत्री द्वय द्वारा संयुक्त उद्घाटन

प्रेरणा भी देता है । "सभी सहभागियों ने अपने-अपने स्थानों से मिट्टी लाकर इस घड्े में एक साथ डाला है, इसलिए यह मिट्टी काफी महत्त्वपूर्ण है, और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसी मिट्टी से हमारा जीवन है ।

सुश्री कार्की ने प्रत्येक अतिथि से आग्रह किया कि वे ललितपुर से लायी हुई मिट्टी' को उस घडे में डालें और इस तरह वे 'मिट्टी मिलन' समारोह के सहभागी हों, साथ ही इस प्रक्रिया के द्वारा यह भी लक्षित हुआ कि वे प्रतिकात्मक रूप से एक साथ कार्यशाला के सहभागी हुए और इतना ही नहीं इस 'मिट्टी मिलन' कार्यक्रम ने वह भी दिखाया कि सम्पूर्ण हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में एक बात सामान्य है और वह बात यह है कि यह क्षेत्र लाखों लोगों को जीवन और महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध कराता है । अर्चनाजी ने इस उद्घाटन सत्र के दौरान श्री एगबर्ट पेलिङ्ग से स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने का आग्रह किया ।

इसीमोड महानिर्देशक एगबर्ट पेलिङ्गका स्वागत संबोधन

श्री पेलिङ्ग ने कहा कि इस कार्यशाला गोष्ठी ने निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों, सामुदायिक वन समूहों और नेटवर्क के सदस्यों और गैर-सरकारी संस्थाओं को एक साथ एकत्रित किया है । प्राकृतिक स्रोत और वातावरण व्यवस्थापन में शासन, विशेषकर विकेन्द्रीकरण और स्थानीय सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में इसीमोड के कोशिशों में यह एक नयी शुरूआत है । इन कुछ वर्षो में निर्णय और योजना निर्माण की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्त्व को पहचाना गया है और साथ ही कुछ प्रश्न एसे भी उभरे है कि इन प्राकृतिक स्रोतों को कैसे और किसके द्वारा उपभोग किया जाए ।

यद्यपि हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में लगातार वातावरण ह्रास दृष्टिगत है, फिर भी इसके विपरीत उत्साह वर्धक आशा की किरण भी नजर आयी है, और यही आशा की किरण इस कार्यशाला गोष्ठीका मुख्य विषय है । श्री पेलिङ्ग ने कहा कि इन पिछले वर्षो में वन स्रोतों के व्यवस्थापन में समुदाय आधारित और अनौपचरिक गाँव स्तरीय संस्थाओं ने अपनी योग्यता को साबित किया है, और साथ ही निर्वाचित गाँव और जिला स्तरीय संस्थाओं के साथ इनकी संलग्नता भी बढ्ती रही है । हिन्दू कुश-हिमालय के विभिन्न देशों में विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया को सहभागी विकास के पूर्वाधार के रूप में प्रस्तुत किया है । विभिन्न निर्वाचित औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं और जरूरतों के प्रस्तुत करने के लिए

'इसिमोड' के महानिर्देशक श्री एगबर्ट पेलिङ्ग द्वारा स्वागत संबोधन ।

लोगों को यह विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया मदद करती है । स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और अनौपचारिक या औपचारिक सामुदायिक वन संस्थाओं के बीच संलग्नता, समन्वय और पारस्परिकता के शर्त नए एवं उभरते हुए थे, इसलिए एक ऐसी कार्यरेखा की आवश्यकता है जो इन दो महत्त्वपूर्ण इकाईयों (स्थानीय निर्वाचित संस्था और अनौपचारिक या औपचारिक सामुदायिक वन संस्था) को एक साथ कर सके । स्थानीय निर्वाचित नेताओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, गाँव वन विकास समितियाँ, महिला मण्डल या दूसरे संबंधित निकाय जो वन व्यवस्थापन में संलग्न हों, इनके बीच संपर्क सहयोग और समन्वय के माध्यम से समानता, पारदर्शिता और कार्यक्षमता के सिद्धान्तो पर आधारित कार्य की रूप रेखा तयार की जाए जो प्राजातांत्रिक शासन को बढावा दे । कार्यशाला गोष्ठी की आयोजना इसलिए की गई है कि स्वयं-निर्भर, आर्थिक रूप से समर्थ पर्वतीय समुदायों को एकत्रित कर ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें स्थानीय विचारो को सुनकर उनका आदर किया जाए और प्राकृतिक स्रोतों को भविष्य संतति के लिए रक्षित और संचित किया जाए ।

श्री पेलिङ्ग ने कहा कि स्थानीय विचारो को निश्चित रूप से सुनने और उस पर विचार के उद्देश्य से कार्यशाला की प्रक्रिया का संचालन अंग्रेजी में नहीं कर हिन्दी, नेपाली और उर्दु में किया जाएगा । उन्होंने कार्यशाला की आयोजना में सहयोग उपलब्ध कराने के लिए यु.एन.डी.पी. जिला विकास समिति नेपाल और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, को धन्यवाद ज्ञापन किया । साथ ही उन्होंने फोर्ड फाउन्डेशन नई दिल्ली, को भी धन्यवाद दिया जो निरन्तर रूप से इसीमोड के सहभागी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम को सहयोग देता आ रहा है ।

श्रीमति केसांग छुन्यालपा, सहायक आवासीय प्रतिनिधि, यु.एन.डी.पी./नेपाल ।

श्रीमति छुन्यालपा ने अपने वक्तव्य के आरंभ में कार्यशाला में उपस्थित अतिथियों से आग्रह किया कि वे प्रमुख रूप से उन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाले जो स्थानीय संस्थाओं और प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के बीच संबंध कायम करते हों । उन्होंने कहा कि स्रोतों के सही परिचालन में कमी ही निर्धनता का मूल कारण है और यही अनुभव यह इंगित करता है कि समुदायों द्वारा विकेन्द्रीकृत प्रशासन प्रक्रिया के माध्यम से स्रोतों को ठीक तरीके से परिचालित किया जा सकता है और इन समुदायों के द्वारा ही इनका अच्छी तरह से व्यवस्थापन किया जा सकता है । स्वशासित सामुदायिक संस्थाएं वहीं पर फैल सकी है जहाँ कि नीतियाँ और दूसरी संस्थाओं ने उनका साथ दिया है नहीं तो सामुदायिक संस्थाएं और स्थानीय सरकार के बीच तथा स्थानीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच का संबंध विवादास्पद ही था । यह आवश्यक है कि स्थानीय समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए नीतियों का निर्माण हो और साथ ही स्थानीय स्तर की छोटी छोटी समस्याओं से भी केन्द्र अवगत रहे । यु.एन.डी.पी. के कार्यक्रमों ने नेपाल में समुदाय, स्थानीय, जिला और केन्द्रीय स्तर की संस्थाओं के बीच संबंध को विकसित

करने का प्रयास किया है । अन्त में श्रीमति छुन्न्याल्पा ने कहा कि यु.एन.डी.पी. इस कार्यशाला गोष्ठी से संबद्ध हो कर काफी प्रसन्न है क्यों कि इस गोष्ठी के माध्यम से इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा । उन्होंने कहा कि वे विश्वस्त हैं कि इस गोष्ठी में होने वाली अर्न्तक्रिया के फलस्वरूप विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया और वन स्रोत व्यवस्थापन के नए आयाम सामने आएंगे ।

माधव पौडेल, अध्यक्ष, जिला विकास समिति संघ, नेपाल (ए.डी.डी.सी.एन) तथा अध्यक्ष, ललितपुर जिला विकास समिति ।

श्री पौडेल ने कहा कि कार्यशाला गोष्ठी के दौरान विचार विमर्श किए जाने वाले मुद्दे न केवल नेपाल के लिए बल्कि इस क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगे । इस कार्यशाला के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने विचार प्रस्तुत करेगें कि किस तरह प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के रास्ते में आने वाले चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए । उन्होंने कहा कि जिला विकास समिति संघ का मुख्य लक्ष्य है, प्रजातंत्र, विकेन्द्रीकरण, जिला स्तरीय शासन, और विकास इन चार प्रक्रियाओं के माध्यम से देश को सहयोग करना ।

नेपाल में जिला विकास समितियाँ विभिन्न कानूनी अड्चनों का सामना करती आ रही है, उन्होने कहा कि उन्हें आशा हैं कि इन कानूनी अड्चनों से संबधित सुझाव जो कि संसद में भेजे जा चुके हैं, निश्चित रूप से पारित होंगे ।

वन स्रोत संबंधी मुख्य मुद्दे पर बात-चीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल में नब्बे प्रतिशत ईन्धन और चालीस प्रतिशत चारा इन वनों से ही उपलब्ध होते है, साथ ही बीहड् जानवरों का वासस्थल है, और भू-स्खलन से बचाव भी ये वन ही करते हैं ।

वातावरण की रक्षा के लिए हमारे सचेत कदम की आवश्यकता है, कि हम किस प्रकार से धरती की रक्षा और वन स्रोतों का उपयोग कर सकते है ?

सामाजिक विकास और सामुदायिक वानिकी में वन की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है साथ ही वन टीम्बर के अतिरिक्त उत्पादों और बाजार बागवानी की भी क्षमता रखता है । सामुदायिक वानिकीं में स्थानीय शासन की भूमिका को निश्चित रूप से इंगित और स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

श्री पौडेल ने कहा की कुछ लोग स्थानीय शासन की भूमिका के प्रति सशंकित है । उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का सामुदायिक वानिकी में राजनीतिकरण उचित नहीं है । निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सामुदायिक वानिकी के नियम एवं कानूनों को लागू एवं विकसित करना तथा विभिन्न

उपभोक्ता समूहों के बीच समन्वय कायम करना ही इन प्रतिनिधियों का मुख्य कार्यक्षेत्र था । चूंकि सम्पूर्ण हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में समस्याएं तकरीबन एक जैसी हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जिला विकास समीती संघ पर्वतीय समस्याओं से संबधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए मुस्तांग जिले में एक कार्यशाला गोष्ठी आयोजित करने का प्रयास कर रहा है । अन्त में उन्होंने माननीय मंत्री वन तथा भू-संरक्षण, से यह आग्रह किया कि स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को अधिक सूविधाजनक बनाने के लिए संसद द्वारा पारित विकेन्द्रीकरण के बील में जिला विकास समीती संघ के विचारों को समाविष्ट करने में मदद करे ।

हरि प्रसाद न्यौपाने, अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, नेपाल ।

श्री न्यौपाने अपने वक्तव्य के आरंभ में ही इस बात पर जोर दिया कि वन विकास, सीमान्त समुदायों के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल सकता है । उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन के पुर्नस्थापना के लिए विभिन्न प्रकार कि इकाईयाँ कार्यरत हैं, जैसे कि वडी परियोजनाएं छोटी संस्थाएं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत प्रयास भी वन संरक्षण में संलग्न हैं ।

उन्होंने इसीमोड को र्काशाला गोष्ठी की आयोजना के लिए धन्यवाद किया । इस गोष्ठी की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहाकि इस कार्यशाला में विभिन्न देशों के सहभागी वानिकी, स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं से संबधित सामान्य संमास्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे । उन्होंनें सामुदायिक वानिकी संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि जबसे नेपाल में नए वन कानून ने सामुदायिक वन और उसके प्रबंध में सहयोग देना शुरू किया है तब से ऐसी जगलें जहाँ कि घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, वहीं अब घना वन है ।

श्री न्यौपाने ने वन और उससे संबंधित अन्य स्रोतों के विकास के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जैसे बच्चे को जन्म देना ही महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसके पालन पोषण की भी आवश्यकता है, उसी तरह वन निर्माण और उसके स्रोतों के संरक्षण की भी आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि वन स्रोत संरक्षण से संबंधित अभी और भी मुद्दे हैं जो सुलझाने बाँकी हैं । समुदायों से संबंधित धारणाओं का खण्डन करते हुए उन्होंनें कहा कि समुदायों ने वन का नाश नहीं किया है, लेकिन यह भी सच है कि केवल वन का परिचालन करना ही पूर्ण नहीं है । वन समुदायों के क्षमता कि कहावत प्रचलित है, "तेता पाँव पसारिये जेती लम्बी सौर", इसलिए समस्याओं की पहचान उनके अपने संदर्भ में होनी चाहिए और उनका समाधान भी व्यावहारिक ही होना चाहिए । जैसे कि ताले को खोलने की तकनीक यदि पता नहीं है तो चाभी का होना भी बेकार है । उन्होंनें कहा कि अधिक उपयुक्त कानून नियम, विनियम आदि के निर्माण और परिचालन के लिए यह आवश्यक है कि वन प्राविधिक और वन उपभोक्ता मिल कर काम करें ।

उन्होंने कहा कि दूसरी समस्या यह थी कि राजनीति ने स्थानीय संस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित किया था और ये संस्थाएं राजनीतिज्ञों के हाथों की औजार बन गई थीं । श्री न्यौपाने ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए । वन समुदायें का स्रोत है, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर इसका उपयोग नहीं होना चाहिए । विदेशों में टिम्बर के निर्यात पर रोक लगना चाहिए । श्री न्यौपाने ने कहा कि उन्हें पूर्ण आशा है कि माननीय स्थानीय विकास मंत्री वन विकास और वन व्यवस्थापन में स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं और वन उपभोक्ता समूह की भूमिकाओं और जिम्मेवारियों को गम्भीरता पूर्वक लेंगे और उनके बीच समन्वय का प्रयास भी करेगे ।

श्री न्यौपाने ने इस बात की पुष्टी की कि वन उपभोक्ता समूहोंमे कानूनी सचेतता अपेक्षाकृत कम ही है । उन्होंने कहा कि 7,000 वन उपभोक्ता समूहों में 6,000 ही प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यरत है और बचे हुए 1,000 वन उपभोक्ता समूह तकरीवन निष्क्रिय ही है । उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि निष्क्रिय संस्थाओं को अनुशासित करे और साथ ही दूसरी संस्थाओं को उत्साहित करें । कहीं-कहीं पर 'वन उपभोक्ता समूह कोष' अच्छी तरह से परिचालित नहीं थे और साथ ही कुछ उपभोक्ता समूह ठीक से व्यवस्थित नहीं थे तथा उनके बीच तारतम्यता का भी अभाव था । इसलिए उपायों और दण्ड की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है । उसी तरह जो उपभोक्ता समूह अच्छी तरह से कार्य कर रहें हो, उन्हें सरकार को चाहिए कि बढावा तथा मदद दे क्योंकि यही उपभोक्ता समूह नेपाल के लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से विकिसित होने में मदद करेंगे ।

सुश्री कार्की ने इसके बाद माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र नारायण सिंह, स्थानीय विकास मन्त्रालय नेपाल, और माननीय मंत्री श्री भक्तबहादुर रोकाया, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, नेपाल को संयुक्त रूप से दीप प्रज्वल्लित करने के लिए आमंत्रित किया जो उन दोनों के कार्य क्षेत्र के संयुक्त रूप का द्योतक था ।

संबोधन भाषण, श्री गजेन्द्र नारायण सिंह, स्थानीय विकास मंत्री, नेपाल ।

श्री सिंह ने कहा कि यद्यपि वन ह्रास की प्रक्रिया नेपाल में कोई नयी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षो में इस प्रक्रिया ने विकराल रूप ले लिया है । यदि समय में ही इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य के स्वरूप की कल्पना असंभव है । उन्होने कहा कि वन ह्रास पर नियंत्रण किसी एक व्यक्ति, वा संस्था यहां तक कि किसी एक देश के द्वारा नहीं किया जा सकता है । उन्होंने कार्यशाला के सहभागियों द्वारा किए गए वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की । वन से संबंधित सभी इकाईयों द्वारा ऐसे प्रयास संयुक्त रूप में एक दूसरे को मदद करते हुए उत्साह एवं सलाह देते हुए, किए जाने चाहिए । सम्पूर्ण विश्व में इस मुद्दे से संबंधित लोगों की

सचेतता को निश्चित रूप से बढाया जाना चाहिए । श्री सिंह इस बात से खुश थे कि वन क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण से संबंधित क्षेत्रीय समाधान ही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है । उन्होंने कहा कि सहयोगी कार्यक्रमों ने वन स्रोतों के व्यवस्थापन में मदद पहुंचाया है । चुँकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों ने नीति नियमों से संबंधित मुद्दों और स्थानीय लोगों के जन जीवन को भी प्रभावित किया है ।

श्री पौडेले द्वारा विकेन्द्रीकरण बील पर उठाए गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्हें आशा है कि जल्द ही यह बील संसद में पारित हो जाएगा । वन व्यवस्थापन के इस क्षेत्र में स्वयं शासन के अभाव में स्थायी वन व्यवस्थापन की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होना कठिन है । नए वन कानून, स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेवारियों को स्पष्ट करें तथा साथ ही लोगों को खुले एवं स्वतंत्र रूप में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करें । उन्होंने कहा कि हिन्दू कुश-हिमाल क्षेत्र के दूसरे देश जैसे कि भारत भी शक्ति विकेन्द्रीकरण को सहभागिता पर आधारित कार्यक्रमों के परिचालन के पूर्वाधार के रूप में ले रहा है । अन्त में उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के समास्याओं के प्रति सचेत है । ये लोग ही नेपाल में बडी संख्या में है साथ ही अपने विकास के प्रति भी सचेत है । श्री सिंह ने आशा व्यक्त कि इस कार्यशाला गोष्ठी में उन मुद्दों पर विचार विमर्श होगा जो हिन्दू कुश क्षेत्र के निर्वाचित इकाईयों और वन उपभोक्ता समूहों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा ।

इसके बाद सुश्री कार्की ने इस कार्यशाला गोष्ठी के विभिन्न देशों के सहभागी प्रतिनिधियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए बारी-बारी से आमंत्रित किया ।

डा. एम. एम. खान, प्राध्यापक, पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन, ढाका विश्वविद्यालय, बांगलादेश ।

डा. खान ने कहा कि इस महत्त्वपूर्ण गोष्ठी में आकर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है । उन्होंने कहा कि दूसरे सहभागियो ने पहले ही बहुत से महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । अब वह दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहते हैं । प्रथमत: यद्यपि स्थानीय निर्वाचित इकाईयाँ मौजूद हैं, फिर भी पूर्ण रूप सें उनमें शक्ति निक्षेपण नहीं हुआ है । साथ ही कुछ मुद्दों में उपयुक्त पैसे, योग्यता और नेतृत्व शक्ति की भी कमी महसूस की गई है । सामुदायिक वानिकी के संबंध में श्री खान ने कहा कि बहुत से नियम कानून अस्पष्ट और अनुपयुक्त हैं, और साथ ही समसामयिक भी नहीं हैं ।

राधा भट्ट, लक्ष्मी आश्रम, अल्मोरा जिला, उत्तर प्रदेश, भारत ।

राधा भट्ट ने हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय लोगों को एक साथ मिल कर महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए इसीमोड को धन्यवाद किया । उन्होंनें अपने सहभागी साथियों से आग्रह किया कि कार्यशाला गोष्ठी के बाद अपने देश और गाँव लौटने पर इस गोष्ठी में हुए निर्णयों एवं निष्कर्षों को वहाँ पर लागू करने का प्रयास करें । वह इस बात से सहमत थीं कि महत्त्वपूर्ण पर्वतीय प्राकृतिक स्रोतों के परिचालन के लिए कडे नियमों का होना जरूरी है, परंतु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गाँव स्तर पर स्वायत्तता के अभाव में केन्द्र के नीति नियम प्रभावकारी नहीं हो सकेंगे । तृण मूल स्तर के लोगों के अनुभवों, सचेतता, स्थान विशेष जानकारी और तीक्ष्णता को पहचाना जाना चाहिए साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए । इस कार्यशाला गोष्ठी में सरकारी और ग्रामीण, दो प्रकार की संस्थाओं से प्रतिनिधि आए हैं । दोनो प्रकार के प्रतिनिधियों का साथ मिल कर विचार विमर्श करना एक ऐतिहासिक शुरूआत है । अपने समुदायों के प्रतिनिधि होने के नाते हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम इस कार्यशाला गोष्ठी को सफल बनाएगें ।

गाणेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, बोखिम गाँव विकास समिति, भोजपुर, नेपाल ।

श्री श्रेष्ठ ने सहभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ मिल कर अपने अपने संस्थाओं और प्राकृतिक स्रोतों के विकास से संबंधित रास्तों को खोजना चाहिए । जैसे कि स्थानीय विकास मंत्री और वन तथा भू-संरक्षण मंत्री ने संयुक्त रूप में दीप जलाकर कार्यशाला का उद्घाटन किया उसी तरह कार्यशाला में उपस्थित दोनों प्रकार की संस्थाओं के प्रतिनिधि साथ मिल कर काम करें । मुद्दा यह था कि किस तरह से स्थानीय, निर्वाचित इकाईयों और वन उपभोक्ता समूह तथा समुदाय आधारित संस्थाओं के बीच सामुदायिक वन को मद्दे नजर रखते हए समन्वय स्थापित किया जाए। कुछ कमजोरियों को पहचाना जा चुका था जैसे कि वैधानिक समस्याएं, राजनीति और वन अधिकारियों तथा तृण-मूल स्तर के लोगों के बीच के संबंध का अभाव । हम इस तरह से साथ मिल कर काम करें ताकि उन समाधानों का खोज करें जो इन कमजोरियों को दूर कर सकें । सामुदायिक वानिकी, स्थानीय लोगों में शक्ति संवर्धन का एक महत्त्पूर्ण साधन था । सामुदायिक वानिकी के विकास में तथा शक्ति संवर्धन में स्थानीय, निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका को पहचानना भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य था ।

'फेकोफन' (सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघ, नेपाल), सामुदायिक वन विकास से संबद्ध है, और वन उपभोक्ता समूह द्वारा सामना किए जाने वाले समस्याओं के समाधान में भी उन्हें सहयोग करता है । हमें इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से 'फेकोफन' को और अधिक शक्ति सम्पन्न और कार्यशील बनाना चाहिए । विशेष रूप से 'गाँव विकास समिति' जिला विकास समिति कानून, और वन कानून के बीच

तारतम्यता के लिए विचार विमर्श करना चाहिए । इन कानूनों ने और प्राधिकृत और जिम्मेवारी संबंधित समस्याएंओं को और अधिक बढावा दिया है । हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य समस्याओं के सामान्य समाधान के खोज की आवश्यकता है ।

मोहम्मद इकबाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी, पाकिस्तान ।

श्री इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों के लोग भी उसी तरह की समस्याओं का सामना करते हैं जैसा कि अन्य सहभागियों ने कहा है । वहाँ भी तृण-मूल स्तर के लोग ही सही अर्थ में वन के उपभोक्ता हैं, लेकिन पेड धीरे - धीरे काटे जा रहे हैं और प्राकृतिक स्रोतों की भी रक्षा उपयुक्त तरीके से नहीं हो पा रही है । अब कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं जैसे कि 'आगा खाँ ग्रामीण सहयोग परियोजना' कुछ नए दृष्टिकोणों को आधार लेकर कार्यशील हैं, साथ ही कुछ सहभागी मूलक प्रक्रियाएं भी उभर रही हैं । उन्होंने कहा कि उनके देशों से आए हुए सहभागी इस कार्यशाला गोष्ठी से सीखना चाहते हैं, और अपने अनुभवों को भी दूसरे देश के सहभागियो के साथ बांटना चाहते हैं । पाकिस्तान के ये सहभागी 'इसीमोड' और यु.एन.डी.पी., से उन कार्यक्रमों में सहययोग की अपेक्षा रखते हैं जो पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में सकारात्मक परिवर्तनों को ला सके ।

इसके बाद सुश्री कार्की ने नेपाल के माननीय वन तथा भू-संरक्षण राज्य मंत्री श्री भक्त बहदुर रोकाया, जो कि इस सभा के अध्यक्ष भी थे, को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित किया ।

भक्त बहादुर रोकाया, माननीय राज्य मन्त्री, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

मंत्री श्री रोकाया ने नेपाल के अपने पडोसी राष्ट्रों के साथ ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के विषय में जानकारी देते हुए संबोधन भाषण आरंभ किया । उन्होने कहा कि इस तरह की कार्यशाला गोष्ठी में वन संरक्षण पर विचार विमर्श करना एक समसामयिक मुद्दा है । उन्होंने आशा व्यक्त कीया कि इस कार्यशाला गोष्ठी के माध्यम से वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के बीच संबंध कायम हो सके, ऐसे रास्ते निकल आएंगे । वानिकी और वन से संबंधित संस्थाओं का राजनीतिक कार्यकलाप वन विकास में बाधा है, यह सिद्ध हो चुका है । साधारणत: नेपाल में यह देखाजा चुका है कि राजनीतिक प्रतिनिधि सामुदायिक वानिकी और वन व्यवस्थापन के संबंध में अपेक्षाकृत कम व्यावहारिक और उदारवादी थे इसी लिए ऐसा सोचकर कि उपभोक्ताओं को वन व्यवस्थापन और विकास में संलग्न किए बिना वन व्यवस्थापन और विकास संभव नहीं है, ऐन कानून में उपभोक्ताओं को उपर्युक्त कार्य की जिम्मेवारी सौंपी गई । लेकिन स्थानीय निर्वाचित नेताओं की भी वन व्यवस्थापन और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है । वन उपभोक्ता समूह और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं

के बीच किसी भी प्रकार के उल्झनों को दूर किया जाना चाहिए । वन व्यवस्थापन और विकास का कार्यभार जब एक बार उपभोक्ता समूह और स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं के हाथ में चला जाता है तो उन्हें चाहिए कि वे मिल कर काम करें क्योंकि दोनो ही संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में संलग्न हैं ।

सामुदायिक वन भी आय आर्जन करने वाले कार्यों को करने में सक्षम है, जैसे कि किमती पेड, जडी बूटी, और अन्य टीम्बर, और वन उतपादन आदि । स्थानीय निर्वाचित इकाईयों को चाहिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में वन उपभोक्ता समूहों को मदद करे ताकि भविष्य में दोनो इकाईयों के बीच संबंध और अधिक सुदृढ हो सकें । यह कार्यशाला गोष्ठी विकेन्द्रीकरण कानून में संशोधन से संबंधित विचारों को आगे लाएगा, ऐसी आशा है ।

जब से स्थानीय लोगों ने वन और वन उत्पादों के महत्व को समझा है वन उत्पादों की चोरी और गैर कानूनी निर्यात कम हो गई है । उन्होंने कहा कि जब वे पिछले वर्ष संसद के सदस्य थे, तब एक प्रस्ताव रखा गया था कि वन स्रोतों से प्राप्त आय को गाँव विकास समिति और जिला विकास समिति को दिया जाएगा । उस समय उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि आय को सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को दिया जाना चाहिए । आगामी जाडे के संसद सत्र में यह प्रस्ताव रखा जाना चाहिए और जो समूह इस प्रस्ताव में रूचि रखते हैं वे अपने परामर्शो के साथ "प्राकृतिक स्रोत एवं पर्यावरण संसदीय समिति" से सम्पर्क करें । श्री रोकाया जी ने यह आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला गोष्ठी से ऐसी नीतियाँ सामने आएंगी जो संबंधित निकायों के बीच सामन्जस्य कायम करने में मदद करेंगी ।

माननीय मंत्री का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए श्रीमति कार्की ने कहा कि श्री रोकाया जी ने कार्यशाला के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्त्व को प्रकाशित करते हुए वन विकास श्रोत विकेन्द्रीकरण से संबंधित समस्याओ तथा समुदायों की भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला है ।

सुश्री कार्की ने सभी वक्ताओं का और साथ ही दूसरे सहयोगी साथियों का जिन्होने इस कार्यशाला गोष्ठी के संचालन में सहयोग दिया था, का धन्यवाद किया ।

सुश्री कार्की ने कहा कि समुदाय ही समाज के आधार हैं, और समुदाय मिल कर ही राष्ट्रस्तम्भ कायम करते हैं । स्वायत्त स्थानीय संस्थाओं और उनके नेताओं ने समुदायों के कार्यकलापों को परिचालित करने में बहुत ही मदद किया है । वन विकास से संबंधित कार्यो में समुदायों की रूचि ने ही सामुदायिक विकास और दीर्घ अवधि वाले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास योजनाओं को जन्म दिया है । ऐसी आशा है कि कार्यशाला में भाग लेने वाले सहभागी हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर के सामुदायिक वन व्यवस्थापन को पनपने और मजबूत होने में अपना योगदान करेंगे ।